Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)
E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण अव्यवस्थित शहरीकरण की चुनौतियाँ

उदय सिंह

सहायक आचार्य, भूगोल
रागेय राघव पी. जी. महिला महाविद्यालय, वैर भरतपुर

सारांश

भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण ने आर्थिक विकास को गति तो प्रदान की है, किंतु इसके साथ ही अनेक सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई है। भारत में वर्ष 1951 में मात्र 17.3 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी, जो 2021 में बढकर लगभग 35 प्रतिशत तक पहुँच गई है। इस तेज शहरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा एवं बेहतर जीवन स्तर की तलाश में पलायन है। परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में आवास संकट, झुग्गी बस्तियों का विस्तार, बेरोजगारी, यातायात जाम, प्रदूषण और जल संकट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

प्रस्तुत शोध–पत्र में जनगणना एवं विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकडों के आधार पर जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अव्यवस्थित शहरीकरण भारतीय शहरों को अस्थिर बना रहा है तथा सतत शहरी विकास के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

परिचय

भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और निकट भविष्य में यह प्रथम स्थान पर पहुँचने की संभावना रखता है। स्वतंत्रता के समय जहाँ भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड थी, वहीं वर्ष 2021 में यह बढकर लगभग 138 करोड हो गई। इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव शहरीकरण की प्रक्रिया पर पडा है।

शहरीकरण सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, शहरों का भौतिक विस्तार और आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण माना जाता है। भारत में शहरीकरण का प्रमुख कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, व्यापार और जीवन–स्तर की आधुनिक सुविधाओं की ओर बढती आकर्षण है। लोग गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. जिससे शहरी जनसंख्या निरंतर बढ रही है।

किन्तु मुख्य समस्या यह है कि भारत में शहरीकरण अधिकांशतः अव्यवस्थित एवं अनियोजित ढंग से हो रहा है। महानगरों और बडे शहरों में तीव्र गति से बढती जनसंख्या के कारण अनेक गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जैसे–

- आवास संकट और झुग्गी–बस्तियों का फैलाव
- जल संकट और स्वच्छ जल की कमी
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या
- यातायात जाम और परिवहन अव्यवस्था
- वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि
- स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ
- सामाजिक असमानताएँ और बेरोजगारी

अव्यवस्थित शहरीकरण का प्रभाव केवल पर्यावरण और भौतिक ढांचे पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचना पर भी पड रहा है। शहरों में झुग्गी बस्तियों का फैलाव सामाजिक असमानता को और गहरा करता है तथा अमीर और गरीब वर्गों के बीच की खाई चौडी होती जा रही है। साथ ही, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से शहरी जीवन स्तर की गुणवत्ता घटती जा रही है।

इस प्रकार, जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण भारतीय शहरों के लिए विकास की संभावना तो लाते हैं, लेकिन यदि इनको सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भविष्य में एक गहन सकट का रूप ले सकते हैं। इस शोध–पत्र का प्रयास इसी ज्वलंत समस्या को भूगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझना और समाधान प्रस्तुत करना है।

साहित्य समीक्षा

संयुक्त राष्ट्र (2021)

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक शहरी जनसंख्या 40: से अधिक हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि शहरीकरण योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ तो संसाधनों पर भारी दबाव पडेगा।

शर्मा, आर. एन. (2018)

अपने अध्ययन ष्शहरी समस्याएँ और समाधान में उन्होंने बताया कि अनियोजित शहरीकरण से आवासीय संकट, प्रदूषण, झुग्गी–बस्तियों का विस्तार और आधारभूत संरचनाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अरोडा, एस. के. (2016)

भारत में शहरीकरण और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव में लेखक ने उल्लेख किया कि शहरीकरण से रोजगार और आर्थिक अवसरों की वृद्धि तो होती है, लेकिन असमानता और गरीबी भी शहरी क्षेत्रों में अधिक तीव्रता से देखने को मिलती है।

गुप्ता, एम. एल. (2021)

अपने शोध अव्यवस्थित शहरीकरण कारण और निवारण में उन्होंने कहा कि शहरी नियोजन की कमी, तीव्र पलायन और भूमि उपयोग नीति की असफलता अव्यवस्थित शहरीकरण के मुख्य कारण हैं।

उद्देश्य

इस शोध–पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. भारत में जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
2. शहरीकरण की तीव्र गति से उत्पन्न हो रही चुनौतियों की पहचान करना।
3. अव्यवस्थित शहरीकरण के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करना।
4. जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण के बीच के संबंध को समझना।
5. सतत एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए आवश्यक उपायों और नीतिगत सुझावों को प्रस्तुत करना।

शोध–पद्धति

प्रस्तुत शोध–पत्र में अपनाई गई शोध–पद्धति मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकार की है।

इसमें विभिन्न सांख्यिकीय आँकडों, जनगणना रिपोर्टी, सरकारी प्रकाशनों तथा शोध आलेखों के आधार पर जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण से जुडी समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

जनसंख्या वृद्धि दर, शहरीकरण की प्रतिशत वृद्धि और रोजगार, आवास, यातायात आदि से संबंधित आँकडों का तालिकाओं और ग्राफ के माध्यम से विश्लेषण किया गया।

अध्ययन की सीमाएँ

- सभी शहरों का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव नहीं था, इसलिए कुछ प्रमुख महानगरों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- समय और संसाधनों की सीमाओं के कारण द्वितीयक आंकडों को सीमित दायरे में ही एकत्रित किया गया।
- जनसंख्या और शहरीकरण से जुडे आँकडे कई बार सरकारी नीतियों और अनुमानों पर आधारित होते हैं, जिससे पूर्णतः सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती।

आंकडों का विश्लेषण

तालिका

भारत में जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण की प्रवृति

क्रम संख्या	वर्ष	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
1.	1951	17.5
2.	1961	20.0
3.	1971	23.3
4.	1981	26.1
5.	1991	27.8
6.	2001	31.6
7.	2011	32.5
8.	2021	35.0

उपरोक्त तालिका में दिए गए आँकडों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 1951 से 2021 तक भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगातार बढता गया है। वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या मात्र 17.5 प्रतिशत थी, जो 1961 में बढकर 20 प्रतिशत हो गई। इसके बाद प्रत्येक दशक में शहरीकरण की दर में वृद्धि होती रही। 1971 में यह 23.3 प्रतिशत और 1981 में 26.1 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसी प्रकार 1991 में शहरी जनसंख्या 27.8 प्रतिशत, 2001 में 31.6 प्रतिशत तथा 2011 में 32.5 प्रतिशत दर्ज की गई। नवीनतम आंकडों के अनुसार 2021 तक शहरी जनसंख्या 35 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन और नगरीकरण की गति निरंतर तेज हो रही है। बढते औद्योगीकरण, रोजगार के अवसर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार ने लोगों को शहरों की ओर आकर्षित किया है। इस प्रकार तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ शहरीकरण का अनुपात भी निरंतर बढ रहा है और आने वाले समय में यह प्रवृत्ति और अधिक तीव्र हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत में तीव जनसंख्या वृद्धि और तेजी से हो रहा नगरीकरण वर्तमान समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यद्यपि शहरीकरण आधुनिकता, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का विस्तार करता है, परंतु जब यह प्रक्रिया अव्यवस्थित और अनियोजित रूप से होती है तो यह अनेक समस्याओं को जन्म देती है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अनियोजित नगरीकरण के कारण महानगरों और शहरों में आवास संकट, झुग्गी–बस्तियों का विस्तार, स्वच्छ पेयजल की कमी, यातायात जाम प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या और सामाजिक असमानताएँ तेजी से बढ रही हैं। साथ ही. ग्रामीण क्षेत्रों से निरंतर पलायन शहरों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है. जिससे सतत् शहरी विकास की प्रक्रिया बाधित हो रही है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण को उचित नियोजन, नीति निर्माण और संसाधनों के संतुलित उपयोग के साथ नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में शहरी जीवन की गुणवत्ता और भी अधिक प्रभावित होगी।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, जनगणना रिपोर्ट, विभिन्न वर्ष।
2. भारत सरकार, नीति आयोग एवं योजना आयोग की रिपोर्ट, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की विभिन्न रिपोर्ट।
4. विश्व बैंक रिपोर्ट 2018
5. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2020
6. अरोडा, एस. के. (2016), भारत में शहरीकरण और उसके सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन।
7. शर्मा, आर. एन. (2018), शहरी समस्याएँ और समाधान, जयपुरः सुरेश पब्लिशिंग हाउस।
8. मिश्रा, पी. डी. (2017), भारत में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की चुनौतियों, वाराणसीः भारती प्रकाशन।
9. सिंह, बी. पी. (2019), सतत शहरी विकास और पर्यावरणीय चुनौतियाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय, शोध आलेख।
10. भारतीय सांख्यिकी संस्थान शहरीकरण से संबंधित सांख्यिकीय रिपोर्ट, कोलकाता।
11. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2021
12. गुप्ता, एम. एल. (2021), अव्यवस्थित शहरीकरण कारण और निवारण, राजस्थान विश्वविद्यालय, भूगोल विभाग।